



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2013/ज्येष्ठ 6, 1935

No. 160]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2013/JYAISTHA 6, 1935

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठा) (डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं) टैरिफ आदेश, 2013

(2013 का 02)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2013

सं. 1-19/2012-बीएंडसीएस.—भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii), (iii) (iv) व (v) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

- (क) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
- (ख) दिनांक 09 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II धारा 3 की उप-धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या -39 (स0क0नि0 44(ई) तथा 45(ई)) के तहत

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

भाग-I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठा) (डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 02) कहा जाएगा।
(2) यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. **अनुप्रयोज्यता**—यह आदेश, संपूर्ण भारत में उपभोक्ताओं को प्रदत्त डायरेक्ट-टु-होम सेवाओं पर लागू होगा।
3. **परिभाषाएं**—इन आदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो: —

- (क) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;
- (ख) "प्राधिकरण" से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (ग) "उपभोक्ता परिसर उपकरण" से आशय किसी एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई किसी प्रसारण सेवा अथवा केबल सेवा की प्राप्ति को समर्थ बनाने के लिए उपभोक्ता के परिसर में स्थापित उपकरण, अवयव और उपांग से है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
- (1) सेट टॉप बॉक्स तथा सेट टॉप बॉक्स के लिए रिमोट कंट्रोल; और
 - (2) डिश एंटीना, जहां ऐसा डिश एंटीना ऐसी सेवा को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, परंतु इसमें टेलीविजन रिसीवर सेट, कम्प्यूटर अथवा ऐसा कोई अंत्य उपकरण शामिल नहीं है;
- (घ) "डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर" से आशय किसी मध्यस्थ, जैसे केबल ऑपरेटर या टेलीविजन चैनलों के किसी अन्य वितरक के माध्यम से न होते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता के परिसर में सीधे ही सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करते हुए केयू बैंड में बहु-चैनल टेलीविजन कार्यक्रमों के संचितरण हेतु लाइसेंस प्रदत्त ऑपरेटर से है ;
- (च) "डायरेक्ट-टु-होम सेवा" का आशय किसी मध्यस्थ, जैसे केबल ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों के किसी अन्य वितरक माध्यम के बिना, उपभोक्ता के परिसरों को सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करते हुए सीधे टीवी सिग्नल उपलब्ध कराकर बहु-चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण करने से है;
- (छ) "आदेश" से आशय दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठा) (डायरेक्ट-टु-होम सेवाएं) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 02) से है;
- (ज) "सामान्य उपभोक्ता" से आशय ऐसे उपभोक्ता से है, जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और उसका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है ;
- (झ) "सेट टॉप बाक्स" का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन से जुड़ा हुआ या उसका भाग होता है; और जो एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता को अनएनक्रिप्टेड और डिस्क्रिम्बल्ड रूप में सब्सक्राइब किए गए चैनल देखने में समर्थ बनाता है;
- (ण) "मानक टैरिफ पैकेज" से आशय, कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट-टु-होम सेवा के सामान्य उपभोक्ता को उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित टैरिफ से है ;
- (ट) इन आदेशों में प्रयुक्त किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम, नियमों और इनके तहत बनाए गए विनियमों या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और नियमों एवं इनके तहत बनाए गए विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और कथनों का अर्थ वही माना जाएगा, जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है।

भाग-II

उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु टैरिफ

4. **उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु टैरिफ.**—(1) प्रत्येक डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) के उपबंधों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित भारतीय मानदण्डों पर खरा-उतारने वाले उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु मानक टैरिफ पैकेज की पेशकश करेगा।
- (2) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) के तहत उपलब्ध विकल्प के अतिरिक्त, सामान्य उपभोक्ता को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर उपभोक्ता परिसर उपकरण की खरीद करने का विकल्प होगा तथा सामान्य उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर, उपभोक्ता द्वारा इंगित परिसर पर उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापन करेगा।

भाग-III

विविध

5. **रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं.**—(1) प्रत्येक डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर, उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु सभी टैरिफ पैकेजों तथा अन्य निबंधन व शर्तों के ब्योरे की दिनांक 15 जून, 2013 तक प्राधिकरण को जानकारी देगा।
- (2) उप-खंड (1) के तहत संसूचित टैरिफ पैकेज में कोई परिवर्तन तथा उपभोक्ता परिसर उपकरण की आपूर्ति और संस्थापन के लिए आरंभ किए गए नए पैकेज की जानकारी ऐसे परिवर्तन या आरंभ किए जाने, जैसा भी मामला हो, के कम से कम सात दिन पूर्व प्राधिकरण को दी जाएगी।

सुधीर गुप्ता, सचिव(आई/सी)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/142/13]

टिप्पणी :-इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (छठा) (डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 02) के उद्देश्य तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

**डीटीएच सेवा हेतु उपभोक्ता परिसर उपकरण की
आपूर्ति और संस्थापना के लिए मानक टैरिफ पैकेज**

(देखें खंड - 4)

विकल्प-1

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति उपभोक्ता परिसर उपकरण का प्रति माह किराया	71.75/-रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा उपभोक्ता परिसर उपकरण, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा।
3	प्रतिभूति जमा राशि (प्रतिदेय)	500/-रुपए
4	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि से कटौती	कुछ नहीं
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

टिप्पणी :-

1. उपभोक्ता परिसर उपकरण संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति होने पर, सामान्य उपभोक्ता को संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस लौटा दी जाएगी ।
2. उपभोक्ता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के अंदर किसी भी समय उपभोक्ता परिसर उपकरण वापस किए जाने पर, बिना कोई कटौती किए संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि वापस लौटा दी जाएगी बशर्ते कि उपभोक्ता परिसर उपकरण से छेड़छाड़ न की गई हो ।
3. कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा कोई संस्थापना प्रभार या पुनः संस्थापना प्रभार नहीं होंगे ।

विकल्प-2

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति उपभोक्ता परिसर उपकरण का प्रति माह किराया	65.50/-रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा उपभोक्ता परिसर उपकरण, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा।
3	प्रतिभूति जमा राशि (समायोज्य)	1000/-रुपए
4	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि से कटौती	कुछ नहीं
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

टिप्पणी :-

1. उपभोक्ता परिसर उपकरण की संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति होने पर, सामान्य उपभोक्ता को संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस लौटा दी जाएगी ।
2. उपभोक्ता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के अंदर किसी भी समय उपभोक्ता परिसर उपकरण वापस किए जाने पर बिना कोई कटौती किए संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि वापस लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि उपभोक्ता परिसर उपकरण से छेड़छाड़ न की गई हो ।
3. कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा कोई संस्थापना प्रभार या पुनः संस्थापना नहीं होंगे ।

विकल्प-3

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति उपभोक्ता परिसर उपकरण का प्रतिमाह किराया	60.66/-रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात	कोई किराया नहीं। स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा उपभोक्ता परिसर उपकरण, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा।
3	प्रतिभूति जमा राशि (समायोज्य)	500/-रुपए
4	उपभोक्ता परिसर उपकरण की वापसी पर वापस लौटाई जाने वाली प्रतिभूति जमाराशि	संलग्न तालिका-क के अनुसार
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

टिप्पणी :-

- यदि कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता परिसर उपकरण की संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी समय, उपभोक्ता परिसर उपकरण को वापस करता है तो, प्रतिभूति राशि को तालिका-क में विनिर्दिष्ट धनराशि के अनुसार वापस किया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता परिसर उपकरण से छेड़छाड़ नहीं की गई हो।
- माह के अंतिम दिन से पूर्व सेवा को काट दिए जाने के मामले में, तालिका-क में उस माह के अंत में वापस के रूप में दर्शायी गई शेष प्रतिभूति जमा राशि को उपभोक्ता परिसर उपकरण की वापसी पर वापस किया जाएगा।
- कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा कोई संस्थापना प्रभार या पुनः संस्थापना नहीं होंगे।

तालिका-क (विकल्प - 3)

आंकड़े - रुपए में

वर्ष	माह के अंत में	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा
प्रथम वर्ष	पहला	488.92
	दूसरा	477.70
	तीसरा	466.33
	चौथा	454.83
	पांचवा	443.18
	छठा	431.39
	सातवा	419.45
	आठवा	407.36
	नौवा	395.12
	दसवा	382.73
	ग्यारहवा	370.18
	बारहवा	357.47
द्वितीय वर्ष	तेरहवा	344.61
	चौदहवा	331.58
	पन्द्रहवा	318.40
	सोलहवा	305.04
	सत्रहवा	291.52
	अठारहवा	277.83
	उन्नीसवा	263.98
	बीसवा	249.94
	इक्कीसवा	235.73
	बाइसवा	221.35

तृतीय वर्ष	तेइसवां	206.78
	चौबीसवां	192.03
	पच्चीसवां	177.10
	छब्बीसवां	161.98
	सत्ताईसवां	146.67
	अट्ठाइसवां	131.18
	उन्नतीसवां	115.48
	तीसवां	99.59
	इकतीसवां	83.51
	बत्तीसवां	67.22
	तैंतीसवां	50.72
	चौंतीसवां	34.03
	पैंतीसवां	17.12
	छत्तीसवां	0.00

विकल्प - 4

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति उपभोक्ता परिसर उपकरण का प्रतिमाह किराया	43.33 रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा उपभोक्ता परिसर उपकरण, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा।
3	प्रतिभूति जमा राशि (समायोज्य)	1000 रुपए
4	उपभोक्ता परिसर उपकरण की वापसी पर वापस लौटाई जाने वाली प्रतिभूति जमाराशि	संलग्न तालिका-ख के अनुसार
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	संक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

टिप्पणी :-

- यदि कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता परिसर उपकरण की संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी समय उपभोक्ता परिसर उपकरण को वापस करता है तो, प्रतिभूति राशि को तालिका-ख में विनिर्दिष्ट धनराशि के अनुसार वापस किया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता परिसर उपकरण से छेड़छाड़ नहीं की गई हो ।
- माह के अंतिम दिन से पूर्व सेवा काट दिए जाने के मामले में, तालिका-ख में उस माह के अंत में प्रतिदाय के रूप में दर्शायी गई शेष प्रतिभूति जमा राशि को उपभोक्ता परिसर उपकरण की वापसी पर वापस किया जाएगा।
- कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा कोई संस्थापना प्रभार या पुनःसंस्थापना नहीं होंगे ।

तालिका-ख (विकल्प - 4)

आंकड़े - रुपए में

वर्ष	माह के अंत में	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा
प्रथम वर्ष	पहला	977.83
	दूसरा	955.39
	तीसरा	932.67
	चौथा	909.66

	पांचवा	886.37
	छठा	862.78
	सातवां	838.90
	आठवां	814.72
	नौवां	790.24
	दसवां	765.45
	ग्यारहवां	740.36
	बारहवां	714.95
द्वितीय वर्ष	तेरहवां	689.22
	चौदहवां	663.17
	पन्द्रहवां	636.79
	सोलहवां	610.09
	सत्रहवां	583.05
	अठारहवां	555.67
	उन्नीसवां	527.95
	बीसवां	499.88
	इक्कीसवां	471.47
	बाइसवां	442.70
	तेइसवां	413.56
	चौबीसवां	384.07
तृतीय वर्ष	पच्चीसवां	354.20
	छब्बीसवां	323.97
	सत्ताईसवां	293.35
	अट्ठाइसवां	262.35
	उन्नतीसवां	230.97
	तीसवां	199.19
	इकतीसवां	167.01
	बत्तीसवां	134.43
	तैंतीसवां	101.45
	चौंतीसवां	68.05
	पैंतीसवां	34.24
	छत्तीसवां	0.00

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

- उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मुख्य क्रिया-कलापों में से एक है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने, ब्रॉडकास्टिंग और केबल टेलीविजन सेवाओं को वहन करने योग्य मूल्य पर उपलब्ध करवाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडकास्टिंग और केबल टेलीविजन क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता विहित मानकों के अनुरूप है, के लिए कई कदम उठाए हैं।
- भारत में डायरेक्ट-टु-होम (डीटीएच) सेवाएं वर्ष 2003 में अपनी शुरुआत से द्रुत गति से बढ़ रही हैं और दिसम्बर 2012 तक पंजीकृत पे-डीटीएच उपभोक्ताओं (उपभोक्ता) की संख्या 54.52 मिलियन के आंकड़ों पर पहुंच गई है। वर्ष 2003 में निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या दो थी, जो अब बढ़कर छह हो गई है। इन ऑपरेटरों ने अपनी सेवाएं भिन्न-भिन्न समय पर शुरू की हैं और इन्होंने विभिन्न ट्रांसमिशन और कम्प्रेसन मानकों और एनक्रिप्शन समाधानों को अपनाया है।

3. डीटीएच सेवाओं में, एक उपभोक्ता को टीवी कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अपने टीवी सैट को उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) से जोड़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके परिसर में प्राप्त सिग्नल डिजिटल और एनक्रिप्टिड रूप में होते हैं। अलग-अलग प्रौद्योगिकियां उपलब्ध होने के कारण, हो सकता है कि एक ऑपरेटर द्वारा लगाया गया सीपीई अन्य ऑपरेटर के नेटवर्क के साथ व्यावहारिक रूप से अनुकूल नहीं हो और सीपीई में पुनः निवेश करे बिना उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के यहां माईग्रेट करने की स्थिति में बाधा उत्पन्न होती है।
4. उपभोक्ता को आसान निर्गमन विकल्प उपलब्ध कराने, उचित मूल्य और शर्तों एवं निबंधनों पर सीपीई की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही, सेवा प्रदाताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए, किराया आधार पर सीपीई उपलब्ध कराने हेतु मानक टैरिफ पैकेज विहित करने वाला एक मसौदा टैरिफ आदेश हितधारकों के साथ चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया था। मसौदा टैरिफ आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2013 को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसके द्वारा हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। इस विचार-विमर्श प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में हितधारकों से कुल 7 टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

हितधारकों की टिप्पणियां :-

5. क्योंकि सीपीई सामान की श्रेणी में आता है न कि सेवा की श्रेणी में, अतः कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने सीपीई हेतु टैरिफ निर्धारित करने के लिए भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाया है।
6. डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा कि चूंकि डीटीएच बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है तथा उपभोक्ता के पास पहले ही सीपीई की एकमुश्त खरीद या किराया खरीद या किराए पर लेने का विकल्प उपलब्ध है, अतः इस स्तर पर भादूविप्रा को सीपीई की कीमतों को विनियमित करने हेतु हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। डीटीएच संघ ने कहा कि प्रस्तावित टैरिफ आदेश, डीटीएच सेक्टर द्वारा वहन की जा रही संचयी हानि में और अधिक वृद्धि कर देगा। आगे, यह भी कहा गया कि सेवा प्रदाताओं के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को सीपीई रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
7. सीपीई की लागत के पहलू पर, ऑपरेटरों ने कहा कि मसौदा टैरिफ आदेश में विचार की गई सीपीई लागत, खरीद, उपभोक्ता के परिसर में सीपीई की संस्थापना एवं सक्रिय करने पर आने वाली वास्तविक लागत से कम है तथा साथ ही कीमतों में भी व्यापक अंतर है। यह भी उल्लेख किया गया कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा सीपीई की पेशकश 1600 रुपए से 2200 रु. के बीच की जा रही है तथा सीपीई पर सब्सिडी 2200 रुपए से 2700 रु. के बीच में है। आगे यह भी कहा गया कि सीपीई की हार्डवेयर लागत 2250 रुपए होती है तथा संस्थापन लागत, डीलर मार्जिन और स्मार्ट कार्ड की लागत 1250 रुपए मानी जानी चाहिए।
8. सीपीई के जीवनकाल के पहलू पर, कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा कि सीपीई के जीवनकाल को 05 वर्ष की जगह 01 वर्ष लिया जाना चाहिए क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किसी भी परिसंपत्ति, जिसकी वास्तविक लागत 5000 रुपए से अधिक नहीं है, पर 100 प्रतिशत वार्षिक मूल्यहास दर की अनुमति है।
9. कुछ डीटीएच ऑपरेटरों ने कहा कि उपभोक्ता के पास सीपीई के गुम होने, क्षति, चोरी के जोखिम की एवज में प्रतिभूति धनराशि, ऑपरेटरों की संरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा इससे उपभोक्ताओं द्वारा सीपीई को वापस करने की चूक में वृद्धि होगी। यह भी कहा गया कि निर्धारित समय से पूर्व समापन शुल्क का प्रावधान होना चाहिए, चूंकि बाजार में 'प्रयोग में लिए गए' सीपीई की कोई स्वीकार्यता नहीं होती।
10. उपभोक्ताओं द्वारा मसौदा टैरिफ आदेश के प्रावधानों का समर्थन किया गया। यह उल्लेख किया गया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं से कोई प्रभार लिए बिना सभी अनुक्षण/ बदलाई/ उन्नयन किया जाना चाहिए। इससे पोर्टेबिलिटी मुद्दे का भी समाधान हो जाएगा और साथ ही उपभोक्ता को सेवा बदलने की लागत के बारे में जानकारी होगी।

टिप्पणियों का विश्लेषण क्षेत्राधिकार

11. डीटीएच और डीएस के लिए सेवा की गुणवत्ता विनियमों के साथ टैरिफ आदेश सभी एड्रैसेबल प्रणालियों पर लागू टैरिफ आदेश में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एड्रैसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योजना, यदि कोई हो, के अनुसार उपभोक्ताओं को एकमुश्त खरीद आधार पर या किराया खरीद आधार पर या किराया आधार पर सीपीई/एसटीबी की खरीद का विकल्प देना होगा। इसके अलावा, विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा परिनियोजित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के कारण, एक उपभोक्ता, जो कि एक विशेष ऑपरेटर की सेवाओं को प्राप्त करने का इच्छुक हो, को सामान्यतः उसी ऑपरेटर से सीपीई प्राप्त करना होता है तथा इस तरह सीपीई, ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई सेवा का अभिन्न भाग बनता है। प्राधिकरण का मत है कि सीपीई के लिए निर्धारित मानक टैरिफ पैकेज, टैरिफ व्यवस्था का अभिन्न अंग है। अतः विनियमों एवं टैरिफ आदेश में पहले ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण ने सीपीई के लिए यह मानक टैरिफ पैकेज तैयार किया है, जिसे सभी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा।

मानक टैरिफ पैकेज निर्धारित करने की आवश्यकता

12. एड्रैसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं को उपभोक्ता के छोर पर प्राप्त करने के लिए सीपीई अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तथापि, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा विविध प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप हो सकता है कि एक ऑपरेटर द्वारा विनियोजित सीपीई, दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क के अनुरूप न हो। इसके कारण किसी एक नए सीपीई पर निवेश किए बिना, उपभोक्ता के चाहने पर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के पास आसानी से स्थानांतरण बाधित होगा।
13. प्राधिकरण का यह मत है कि इस संबंध में उपभोक्ताओं के हितों को सीपीई के वाणिज्यिक अंतःप्रचालन के उपबंध के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। अगर उपभोक्ता ऑपरेटर को किसी कारणवश बदलना चाहे तो, वाणिज्यिक अंतःप्रचालनता उसे एक निर्गमन का एक विकल्प प्रदान करती है। तदनुसार, भादूविप्रा के संगत विनियमों/टैरिफ आदेशों में यह अनिवार्य किया गया था कि डिजिटल एड्रैसेबल प्रणालियों के ऑपरेटर प्रत्येक उपभोक्ता को सीपीई या तो एकमुश्त खरीद आधार अथवा किराया खरीद आधार पर अथवा किराए पर अथवा प्राधिकरण द्वारा विहित किसी योजना के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करे।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डीटीएच सेवाओं के मामले में डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को पेश की जा रही सीपीई योजनाओं में काफी भिन्नता है तथा कभी-कभार उपभोक्ताओं के पास कोई व्यवहारिक निर्गमन विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इससे उपभोक्ताओं को किसी एक विशिष्ट ऑपरेटर अथवा प्लेटफार्म से स्थानांतरण पर, नए हार्डवेयर पर पुनर्निवेश करना होता है।
15. उपरोक्त के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को सुगम निर्गमन विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, उचित लागत तथा निबंधन एवं शर्तों पर सीपीई की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा साथ ही साथ सेवा प्रदाता के हितों की रक्षा करने के लिए, सीपीई को किराया आधार पर पेश करने हेतु मानक टैरिफ पैकेज विहित करते हुए यह टैरिफ आदेश निर्धारित किया जा रहा है।
16. प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए मानक टैरिफ पैकेज के अतिरिक्त मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेशों के अनुसार ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को सीपीई की आपूर्ति करने के लिए अपनी योजनाओं के प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं और उपभोक्ताओं के पास प्राधिकरण द्वारा विहित मानक टैरिफ पैकेज तथा ऑपरेटरों द्वारा पेश की जा रही वैकल्पिक योजनाओं में से चयन करने का विकल्प होगा। विहित मानक टैरिफ पैकेज उपभोक्ता को स्पष्ट समझने के लिए आसान निबंधन व शर्तों के साथ सीपीई उपलब्ध कराता है साथ ही उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरता है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि मानक टैरिफ पैकेज विहित करने से संपूर्ण क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा वाणिज्यिक अंतःऑपरेटरता को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराएगा।
17. प्राधिकरण ने यह पाया है कि ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के एसटीबी की पेशकश कर रहे हैं जिनकी मूलभूत कार्यकरण के अतिरिक्त अलग-अलग विशेषताएं/क्षमताएं हैं जैसे "रिकॉर्डिंग सुविधा", "इंटरनेट/ब्रॉडबैंड संयोज्यता", "हार्ड डेफिनिशन/3-डी-रिसेप्शन" सुविधा आदि हैं। चूंकि ऐसे एसटीबी के लिए विशेषताओं तथा लागत के संदर्भ में काफी अंतर होगा और इसलिए केवल मूलभूत/आधारभूत एसटीबी के लिए ही मानक टैरिफ पैकेज उपलब्ध कराया गया है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित संगत भारतीय मानक के अनुरूप मानक डेफिनिशन टीबी सिगनल (एसडीटीबी) की प्राप्ति के लिए बनाया गया है।
18. प्राधिकरण का मत है कि मानक टैरिफ पैकेज को विहित किए जाने से ऑपरेटरों के मध्य उपभोक्ताओं को वहनीय दर पर बेहतर टेलीविजन देखने का अनुभव उपलब्ध कराने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा ताकि मौजूदा उपभोक्ताओं को बनाए रखा जा सके और साथ ही नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जा सके। ऐसी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं सहित इस क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ पहुंचेगा।

मानक टैरिफ पैकेज विहित करने के लिए ध्यान में रखी गई एसटीबी की लागत

19. परामर्श-पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों में, सीपीई की लागत 3500 से 5000 रु. के मध्य सुझाई गई, जिसमें संस्थापना तथा सक्रियण प्रभार शामिल हैं। तथापि, मसौदा टैरिफ आदेश तैयार करने से पूर्व भादूविप्रा के प्रश्नों पर, डीटीएच संघों ने सीएस/मिडलवेयर एवं संस्थापना लागत सहित सीपीई की लागत लगभग 2860/-रुपए बताई गई। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्राधिकरण के पास प्रस्तुत नवीनतम पीएमआर में, एक डीटीएच ऑपरेटर द्वारा संस्थापना आदि जैसे अपफ्रंट प्रभार सहित एकमुश्त खरीद पर सीपीई (एमपीईजी4, डीवीबीएस2) को 2500 रुपए के अंदर उपलब्ध कराने की सूचना दी है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक मर्दों की लागत समय के साथ निरंतर गिर रही है। उपरोक्त के आलोक में मानक टैरिफ पैकेज तैयार करने के लिए एसटीबी की लागत 2250 रुपए मानी गई है।

सीपीई/एसटीबी का जीवनकाल

20. हितधारकों, विशेषकर डीटीएच ऑपरेटरों ने उल्लेख किया है कि सीपीई के जीवनकाल को 05 वर्ष की बजाए 01 वर्ष मानना चाहिए, चूंकि कंपनी अधिनियम, 1956 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी परिसंपत्ति, जिसकी वास्तविक लागत 5000 रुपए से अधिक हो पर अनुमेय वार्षिक मूल्यहास दर शत-प्रतिशत है। डिजिटल एड्रैसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएस) के मामले में हितधारकों ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान उल्लेख किया कि विनिर्माता सामान्यतः एसटीबी के लिए 12 से 18 माह तक की अवधि की वारंटी उपलब्ध करा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि डीटीएच प्लेटफार्म हेतु एसटीबी/सीपीई के मामले में यह बात लागू होनी चाहिए। प्राधिकरण ने भी इस बात पर तथा साथ ही साथ इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि समय के साथ प्रौद्योगिकियों तथा इलेक्ट्रॉनिक मर्दों की सुदृढ़ता में काफी सुधार हुआ है। तथापि, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक मर्दों के निष्पादन तथा विशेषताओं के संदर्भ में सुधार हुआ है और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आने के साथ ही पुराने उत्पादन उपयोग से हटते जाते हैं। यही बात सीपीई/एसटीबी के मामले में सटीक बैठती है। इसलिए, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए सीपीई के जीवनकाल को 03 वर्ष माना गया है।

सीपीई की वापसी

21. एक एड्रैसेबल प्रणाली में सीपीई को उपभोक्ता द्वारा केवल तभी उपयोग किया जा सकता है यदि इसे, उसके सेवा प्रदाता द्वारा उसके नेटवर्क में उपयोग हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई उपभोक्ता उस एसटीबी और सीपीई के अन्य कल-पुर्जों को अपने कब्जे में रख लेगा, जिनकी उसके लिए कोई उपयोगिता न हो, विशेषकर अन्य ऑपरेटर/प्लेटफार्म में स्थानांतरण पर जाने अथवा उस ऑपरेटर की सेवाओं से हटने की स्थिति में, जब यह धरोहर राशि के वापस लौटाने से संबद्ध होगा। इसके आलोक में एसटीबी की वापसी न किए जाने के संबंध में ऑपरेटरों की आशंकाएं मान्य नहीं हैं।

मानक टैरिफ पैकेज को तैयार करने हेतु उपयोग किए गए मानदण्ड

21. मानक टैरिफ पैकेज को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है :-

- (1) सीपीई की कुल लागत 2250/-रुपए मानी गई है ।
- (2) सीपीई के जीवनकाल को 03 वर्ष माना गया है ।
- (3) अवशिष्ट मूल्य को शून्य माना गया है ।
- (4) प्रतिमाह किराया 36 माह की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर (1.25 प्रति माह की दर पर) समान मासिक किस्त (ईएमआई) पर सीपीई की प्रतिमाह लागत पर आधारित है ।
- (5) उन विकल्पों में जहां धरोहर जमा राशि का प्रतिदाय किया जाना है, धरोहर जमा राशि पर ब्याज को किराए में समायोजित कर लिया गया है ।
- (6) उन विकल्पों में जहां धरोहर जमा राशि को समायोजित करना हो, वहां शेष धरोहर जमा राशि पर प्रतिमाह ब्याज को किराए में समायोजित कर लिया गया है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (Sixth) (THE DIRECT TO HOME SERVICES) TARIFF ORDER, 2013 (No. 2 OF 2013)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2013

No. 1-19/2012-B&CS.—In exercise of powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44 (E) and 45 (E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii),---

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order, namely:—

PART-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Sixth) (The Direct to Home Services) Tariff Order, 2013 (No. 2 of 2013).

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Applicability.---This order shall be applicable to direct to home services provided to the subscribers throughout the territory of India.

3. Definitions.--- In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(b) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(c) “Customer Premises Equipment” means the equipment, components and accessories installed at the premises of the subscriber to enable the reception of any broadcasting service offered through an addressable system and includes ---

(i) the set top box and the remote control for set top box; and

(ii) the dish antenna, where such dish antenna is essential for availing such service,—

but shall not include a television receiver set, computer or any such end equipment;

(d) “direct to home operator” means an operator licensed by the Central Government to distribute multi channel TV programmes in Ku band by using a satellite system directly to subscriber’s premises without passing through intermediary such as cable operator or any other distributor of TV channels;

- (e) “direct to home service” means distribution of multi channel TV programmes by using a satellite system by providing TV signals directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary such as cable operator or any other distributor of TV channels;
- (f) “order” means the “Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Sixth) (The Direct to Home Services) Tariff Order, 2013 (No. 2 of 2013)”;
- (g) “ordinary subscriber” means any subscriber who receives a programming service from a service provider and uses the same for his domestic purposes;
- (h) “set top box” means a device, which is connected to, or is part of a television and which allows a subscriber to receive in unencrypted and descrambled form subscribed channels through an addressable system;
- (i) “standard tariff package” means a tariff determined by the Authority for supply and installation of a customer premises equipment to the ordinary subscriber of direct to home service for receiving programmes;
- (j) all other words and expression used in this order but not defined, and defined in the act and rules and regulations made thereunder or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and the rules and regulations made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

PART II

TARIFF FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT

4. Tariff for supply and installation of Customer Premises Equipment.— (1) Every direct to home operator shall, without prejudice to the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (No.1 of 2010), offer to every ordinary subscriber the standard tariff package, for supply and installation of the Customer Premises Equipment, conforming to the Indian Standard, if any, set by the Bureau of Indian Standard, specified in the Schedule.

(2) In addition to the option available under the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (No.1 of 2010), the ordinary subscriber shall have option to acquire the Customer Premises Equipment at the rate and the terms and conditions specified in the Schedule and the direct to home operator shall, on receipt of request from the ordinary subscriber, supply and install the Customer Premises Equipment at the premises indicated by the subscriber.

PART III

MISCELLANEOUS

5. Reporting Requirement.—(1) Every direct to home operator shall report to the Authority by the 15th of June 2013, the details of all tariff packages and other terms and conditions for supply and installation of the Customer Premises Equipment.

(2) Any change in the tariff package reported under sub-clause (1) and the introduction of a new tariff package for supply and installation of the Customer Premises Equipment shall be reported to the Authority at least seven days prior to such change or introduction, as the case may be.

SUDHIR GUPTA, Secy. (I/C)

[ADVT III/4/Exty./142/13]

Note :—The Explanatory Memorandum annexed to this order explains the objects and reasons of “The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Sixth) (The Direct to Home Broadcasting Services) Tariff Order, 2013 (No. 2 of 2013)”.

SCHEDULE

**Standard Tariff Package for Supply and Installation of
Customer Premises Equipment for DTH service
(see clause 4)**

OPTION – I

Sl.	Particulars	Tariff
1.	Rent per month per Customer Premises Equipment for the first three years	Rs. 71.75 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The Customer Premises Equipment shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Refundable)	Rs. 500/-
4.	Deduction from Refundable Security Deposit	Nil
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

Note :—

1. After the expiry of three years from the date of installation of Customer Premises Equipment, the entire security deposit shall be refunded to the ordinary subscriber without any deductions.
2. The full security deposit without any deduction shall be refunded to the subscriber, if he returns the Customer Premises Equipment, at any point of time, within a period of three years, provided that the Customer Premises Equipment has not been tampered with.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

OPTION – II

Sl. No.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per Customer Premises Equipment for the first three years	Rs. 65.50 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The Customer Premises Equipment shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card

3.	Security Deposit (Refundable)	Rs. 1000/-
4.	Deduction from Refundable Security Deposit	Nil
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

Note :—

1. After the expiry of three years from the date of installation of Customer Premises Equipment, the entire security deposit shall be refunded to the ordinary subscriber without any deductions.
2. The full security deposit without any deduction shall be refunded to the subscriber if he returns the Customer Premises Equipment, at any point of time, within a period of three years, provided that the Customer Premises Equipment has not been tampered with.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

OPTION – III

Sl. No.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per Customer Premises Equipment for the first three years	Rs. 60.66 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The Customer Premises Equipment shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Adjustable)	Rs. 500/-
4.	Amount of Security Deposit refunded on return of the Customer Premises Equipment	As per attached Table-A
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

Note: —

1. If the ordinary subscriber returns the Customer Premises Equipment, any time before the completion of three years from the date of installation of Customer Premises Equipment, the Security Deposit shall be refunded as per the amount specified in the Table-A, provided that the Customer Premises Equipment is not tampered with.
2. In case of disconnection of direct to home service before the last day of the month, balance security deposit shown as refundable at the end of that month, in Table-A shall be refunded on return of Customer Premises Equipment.

3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

Table-A (OPTION-III)*Figure in Rs.*

Year	End of Month	Security deposit refundable
First year	First	488.92
	Second	477.70
	Third	466.33
	Fourth	454.83
	Fifth	443.18
	Sixth	431.39
	Seventh	419.45
	Eighth	407.36
	Ninth	395.12
	Tenth	382.73
	Eleventh	370.18
	Twelfth	357.47
Second year	Thirteenth	344.61
	Fourteenth	331.58
	Fifteenth	318.40
	Sixteenth	305.04
	Seventeenth	291.52
	Eighteenth	277.83
	Nineteenth	263.98
	Twentieth	249.94
	Twenty first	235.73
	Twenty second	221.35
	Twenty third	206.78
	Twenty fourth	192.03
Third year	Twenty fifth	177.10
	Twenty sixth	161.98
	Twenty seventh	146.67
	Twenty eighth	131.18
	Twenty ninth	115.48
	Thirtieth	99.59
	Thirty first	83.51
	Thirty second	67.22
	Thirty third	50.72
	Thirty fourth	34.03
	Thirty fifth	17.12
	Thirty sixth	0.00

OPTION – IV

Sl. No.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per Customer Premises Equipment for the first three years	Rs. 43.33 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The Customer Premises Equipment shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Adjustable)	Rs. 1000/-
4.	Amount of Security Deposit refunded on return of the Customer Premises Equipment	As per attached Table-B
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

Note: -

1. If the ordinary subscriber returns the Customer Premises Equipment, any time before the completion of three years from the date of installation of Customer Premises Equipment, the Security Deposit shall be refunded as per the amount specified in the Table-B, provided that the Customer Premises Equipment is not tampered with.
2. In case of disconnection of direct to home service before the last day of the month, balance security deposit shown as refundable, at the end of that month, in Table-B shall be refunded on return of Customer Premises Equipment.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

Table-B (OPTION-IV)*Figure in Rs.*

Year	End of Month	Security deposit refundable
First year	First	977.83
	Second	955.39
	Third	932.67
	Fourth	909.66
	Fifth	886.37
	Sixth	862.78
	Seventh	838.90
	Eighth	814.72
	Ninth	790.24
	Tenth	765.45
	Eleventh	740.36

	Twelfth	714.95
Second year	Thirteenth	689.22
	Fourteenth	663.17
	Fifteenth	636.79
	Sixteenth	610.09
	Seventeenth	583.05
	Eighteenth	555.67
	Nineteenth	527.95
	Twentieth	499.88
	Twenty first	471.47
	Twenty second	442.70
	Twenty third	413.56
	Twenty fourth	384.07
Third year	Twenty fifth	354.20
	Twenty sixth	323.97
	Twenty seventh	293.35
	Twenty eighth	262.35
	Twenty ninth	230.97
	Thirtieth	199.19
	Thirty first	167.01
	Thirty second	134.43
	Thirty third	101.45
	Thirty fourth	68.05
	Thirty fifth	34.24
	Thirty sixth	0.00

Annexure**Explanatory Memorandum**

1. Consumer protection is one of the focus areas of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). The Authority has taken several measures to protect the interest of the consumers, facilitate availability of broadcasting and cable television services at affordable price and to ensure that Quality of Service being provided to the consumer in the broadcasting and cable television sector is in accordance with the prescribed norms.
2. Direct to home (DTH) services in India have been growing at a rapid pace since its inception in the year 2003, and, as on December 2012, the number of registered pay DTH subscribers has reached a figure of 54.52 million. The number of private DTH operators has also grown from two in the year 2003 to six operators now. These operators have launched their services at different points of time, deploying different transmission and compression standards and encryption solutions.
3. In DTH services, a subscriber need Customer Premises Equipment (CPE) to be connected with his TV set for reception of TV programmes as the signal received at his premises is in digital and encrypted form. Since variegated technologies co-exist, the CPEs deployed by one operator may not be practically compatible with the network of another operator, hampering easy migration of the subscriber from one operator to another, in case the subscriber wishes to do so, without re-investing in new CPE.
4. To provide an easy exit option to the subscribers, ensure availability of CPEs at reasonable price and terms and conditions and, at the same time, to protect the interests of the service providers, a draft tariff order, prescribing

standard tariff package for offering of CPE on rental basis, was put up for consultation with the stakeholders. The draft tariff order was uploaded on TRAI website on 11th April 2013, inviting the comments from the stakeholders. In response to this consultation process, a total of 7 comments were received from the stakeholders.

Comments of stakeholders

5. Some of the DTH operators have questioned the jurisdiction of TRAI to fix the tariff of CPEs as CPEs come under the category of goods and not services.
6. DTH operators have argued that as the DTH market is highly competitive and consumer already has choice to get CPE on outright purchase or hire-purchase or rental basis, therefore, there is no need for TRAI to intervene at this stage to regulate the prices of CPE. DTH association has stated that the proposed tariff order would add to the accumulated losses being suffered by the DTH sector. It has further stated that DTH operators are providing CPE to customers at subsidised rates due to intense competition between the service providers.
7. On the aspect of cost of CPE, the operators have stated that the cost of CPE considered in the draft tariff order is lesser than the actual cost in procuring, activating and installing of CPE at the subscriber's premises and also there is wide variation in the prices. It has been mentioned that DTH operators are offering CPEs between Rs.1600 to Rs. 2200 and the subsidy on CPE is in the range of Rs. 2200 to Rs. 2700. It has also been stated that the hardware cost of CPE works out to be Rs. 2250 and installation cost, dealer margin and cost of smart card should be taken as Rs. 1250.
8. On the aspect of life span of CPE, some of the DTH operators have stated that the life span of CPE should be taken as 1 year instead of 5 years since under the Companies Act, 1956 and Income Tax Act, 1961, the annual depreciation rate, allowed on any asset whose actual cost does not exceed Rs.5000, is 100%.
9. Some of the DTH operators have stated that the amount of security deposit is not sufficient to protect the operators against risk of loss, damage, theft of CPE at the consumer end and this will lead to increase in consumer defaults in returning the CPE. It has been stated that there should be a provision of early termination charges as the "used" CPEs do not have any acceptance in the market.
10. Consumers have supported the provisions of the draft tariff order. It has been mentioned that all maintenance/replacement/upgradation should be done by the service provider, without any charge to the consumer. This will take care of the portability issue as well, as consumer will know the cost of changing service.

Analysis of the comments

Jurisdiction

11. The quality of service regulations for DTH and DAS as well as tariff order applicable for all the addressable systems, clearly provides that the service providers providing broadcasting and cable TV services using an addressable system are required to give option to the subscribers for procuring the CPE/STB on outright purchase basis or hire purchase basis or rental basis as per the scheme, if any, made by the Authority in this behalf. Moreover, due to variegated technologies deployed by different operators, a consumer desiring services of a particular operator generally needs to get the CPE from that operator and so, the CPE forms an integral part of the services provided by the operator. The Authority is of the view that the standard tariff of package prescribed for CPE is part and parcel of tariff dispensation. Therefore, in accordance with the provisions already made in the regulations and tariff order, the Authority has come up with this standard tariff package for the CPEs which is to be mandatorily offered by all the DTH operators to their subscribers.

Need for prescribing the standard tariff package

12. CPE is necessarily required at the consumer end for receiving the services offered by a service provider offering broadcasting and cable TV services using addressable system. However, different service providers are deploying different technologies and as a result, the CPEs deployed by one operator may not be compatible with the network of another operator, hampering easy migration of the subscriber from one operator to another, in case the subscriber wishes to do so, without re-investing in a new CPE.

13. The Authority is of the view that the interests of the consumers in this regard can be largely protected through the provision for commercial interoperability of CPE. The commercial interoperability provides an exit option for a subscriber in case the subscriber wishes to change the operator for any reason. Accordingly, in the relevant Regulations/Tariff orders of TRAI, it was mandated that the operators of Digital Addressable Systems shall give an option to every subscriber to procure the CPE either on outright purchase basis or hire purchase basis or rental basis, or in accordance with the scheme, if any, prescribed by the Authority.
14. As mentioned above, in case of DTH services, the schemes for CPEs offered to the subscribers by the DTH operators, have wide variations and at times are such that no viable exit option is available to the subscribers. Instead the consumer has to re-invest in new hardware in case of migration from a particular operator or platform.
15. In view of the above, to provide an easy exit option to the subscribers, ensure availability of CPEs at reasonable cost and terms and conditions and, at the same time, to protect the interest of the service providers, this tariff order prescribing standard tariff package for offering of CPE on rental basis is being prescribed.
16. In addition to the standard tariff packages prescribed by the Authority, the operators are free to offer their own schemes for supply of CPE to its subscribers in accordance with the existing Regulations/Tariff Orders and the subscribers shall have option to choose from the Standard Tariff Package prescribed by the Authority and the alternative schemes offered by the operators. The prescribed standard tariff package enables the subscriber to procure the CPE with clear, easy to understand, terms and conditions and meets the requirement of consumers as well as the service providers. Therefore the Authority is of the view that prescribing the Standard tariff package would benefit the sector as a whole and would provide effective commercial interoperability.
17. The Authority has observed that the operators are offering to its subscribers various types of STBs having different features/capabilities such as “recording facility”, “Internet/broadband compatibility”, “ High definition/3D reception capability” etc., in addition to the basic functionalities. Since for such STBs there would be wide variations in terms of features and cost and hence the Standard Tariff Package is provided only for the basic/vanilla STBs meant for reception of Standard Definition TV signals (SDTV) conforming to the relevant Indian Standard, if any, set by the Bureau of Indian Standards.
18. The Authority is of the view that prescription of a Standard Tariff Package would promote healthy competition amongst the operators to provide better viewing experience to the consumer at an affordable price so as to retain the existing consumer as well as to rope in new ones too. Such competition would ultimately benefit all the stakeholders of the sector including the consumers.

Cost of STB considered for prescribing the standard tariff package

19. In the comments received in response to the consultation paper, the cost of the CPE suggested, ranges from Rs. 3500 to Rs. 5000, including the installation and activation charges. However, in response to a query from TRAI, prior to formulation of the draft tariff order, the DTH Association informed the cost of the CPE to be around Rs. 2860, including the costs of CAS/middleware and installation. In the latest PMR, filed by the DTH operators to the Authority, one DTH operator has reported to be offering CPE (MPEG4, DVBS2) under outright purchase within Rs. 2500, including other upfront charges like installation charges, etc. The cost of electronic items, in general, is consistently falling with time. In view of the above, the cost of CPE has been taken as Rs 2250/- for the purpose of formulation of the Standard Tariff Package.

Lifespan of CPEs/STBs

20. The stakeholders particularly DTH operators have stated that the lifespan of CPEs should be taken as one year instead of five years. Since under the Companies Act, 1956 and Income Tax Act, 1961, the annual depreciation rate, allowed on any asset whose actual cost does not exceed Rs. 5000, is 100%. In case of Digital Addressable Cable TV Systems (DAS), the stakeholders during the consultation process, have stated that the manufacturers are generally providing warranty for a period ranging from 12 to 18 months for the STBs. It is expected that the same should also hold good in case of the STBs /CPEs for DTH platform. The Authority has also taken note of this and also the fact that with passage of times the technology and therefore the robustness of electronic devices has improved considerably. However, at the same time, the technology is changing at a fast pace and

continuously there is improvement in terms of performance and features of the electronic items and with introduction of better electronic products the older ones tend to become obsolete. The same holds good for the CPEs/ STBs also . Therefore, taking these factors into account the lifespan of the CPEs has been taken as three years.

Returning of CPEs

21. A CPE in an addressable system can only be used by a subscriber if it has been duly authorized by its service provider for use in its network. It is unlikely that a subscriber would withhold the STB and other components of CPE without any utility for him. More so, when it is linked to the refund of the security deposit in the event of migration to other operator/platform or quitting from the subscription of that operator's services. In view of this the apprehensions of the operators with respect to non-returning are not tenable.

Parameters used to formulate the standard tariff package

22. The Standard Tariff Package has been worked out on the basis of the following parameters:—

- i. The total cost of CPE has been taken as Rs. 2250/-
- ii. Life span of CPE has been taken as 3 years.
- iii. The residual value has been taken as nil.
- iv. Rental per month is based on cost of CPE on Equated Monthly Installment (EMI) Basis @15% per annum (@1.25% per month) for a period of 36 months.
- v. In options where the security deposit is to be refunded, the interest on security deposit has been adjusted in the rental.
- vi. In options where the security deposit is to be adjusted, the interest per month on balance security deposit has been adjusted in the rental.